# इकाई 16 कल्याणकारी राज्य

**इकाई की रूपरेखा**


16.1 प्रस्तावना

16.2 सकारात्मक उदारवाद का विकास

16.3 उदारवादी लोकतान्त्रिक - कल्याणकारी राज्य

16.3.1 कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है

16.3.2 कल्याणकारी राज्य एक लोकतान्त्रिक राज्य है

16.3.3 कल्याणकारी राज्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है

16.3.4 कल्याणकारी राज्य समाज की एक स्थायी संस्था तथा उसका एक तटस्थ अभिकरण है

16.4 कल्याणकारी राज्य की औचित्यता

16.4.1 राज्य और बाज़ार

16.4.2 व्यक्तिवादी

16.4.3 वैयक्तिक स्वतंत्रता की संवृद्धिता

16.4.4 समानता

16.4.5 अधिकार

16.4.6 नागरिकता

16.4.7 न्याय

16.5 कल्याणकारी राज्यः समसामयिक विवाद

16.6 कल्याणकारी राज्य में विपत्तिः एक समीक्षात्मक मूल्यांकन

16.7 सारांश

16.8 अभ्यास प्रश्न


## 16.1 प्रस्तावना

'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा में सामाजिक नीतियों के एक विस्तृत क्षेत्र का बोध मिलता है। ऐसी नीतियों में समय अनुसार मूल सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा को राज्य द्वारा सामान्यतः निःशुल्क उपलब्ध कराना सम्मिलित होता है। इसका क्षेत्र कभी कभी सामाजिक सुरक्षा तक विस्तृत हो जाता है, जिसके अंतर्गत हित लाभ हेतु लोगों को भी कानूनन योगदान देना पड़ता है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त सकारात्मक उदारवाद का आधार है। यह एक ऐसा राज्य है, जो सभी नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएँ प्रदान करता है, कमज़ोर वर्गों का संरक्षण करता है, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, तथा अमीर व गरीब में अन्तर को कम करने का प्रयास करता है। यह अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाता है, उद्योगों का रा-ट्रीयकरण करता है, कमज़ोर वर्गों की रक्षा हेतु कानूनों का निर्माण करता है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंध करता है, आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने देता तथा प्रगामी करारोपण एवं आय पुनः वितरण माध्यमों द्वारा अमीर तथा गरीब के बीच दूरी कम करने का यत्न करता है तथा समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य पैदा करता है।

निर्धनता, निरक्षरता, बेरोजगारी तथा शो-ण को नियंत्रित कर सकता है; राज्य के सकारात्मक कार्यों द्वारा अमीर तथा गरीब के अन्तर को कम किया जा सकता है। *चौथा,* राजनीतिक स्तर पर, सकारात्मक उदारवाद इस तथ्य पर आधारित है कि सामान्य हित अथवा सामान्य कल्याण का भाव राजनीति का एक प्रभावकारी प्रयोजन है। कल्याणकारी विधेयक द्वारा राज्य मानव-व्यक्तित्व के विकास का एक यंत्र है; राज्य का स्वरूप सकारात्मक होता है और फिर वह सामाजिक रूप से लाभकारी कार्य करने में सक्षम होता है। लोकतंत्र, प्रतिनिधिक सरकार, संवैधानिकवाद, संसदीय प्रयोजन, सार्वजनिक मताधिकार, दलीय संगठन आदि ऐसी कुछ संस्थात्मक व्यवस्थाएँ हैं; जिनके माध्यम से वैयक्तिक हित की प्राप्ति हो सकती है; उदारवादी सरकार वह होती है जो व्यक्ति तथा समाज के अधिकारों का संरक्षण करती है; राज्य को समाज के वर्गों के भिन्न हितों में समन्वय पैदा करना होता है; यह समाज के किसी वर्ग विशे-ा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु समस्त रूप से पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

## 16.3 उदारवादी लोकतान्त्रिक - कल्याणकारी राज्य

20वीं शताब्दी में सकारात्मक उदारवाद की पहचान लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्य से की जाने लगी। कल्याणकारी राज्य के विचार में 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद अहस्तक्षेपी राज्य में मौलिक परिवर्तन किए जाने के संकेत थे। इनका सम्बंध सार्वजनिक नीति के क्षेत्र, राज्य गतिविधियों का स्वरूप, मानव प्रकृति की मूल मान्यताएँ तथा सामाजिक हित के विचार आदि में परिवर्तनों से था। कल्याणकारी राज्य का प्रयास व्यक्ति के हितों तथा समाज के हितों को एक दूसरे के अनुरूप बनाए रखने का यत्न था, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था के अनिवार्य लक्षण भी बने रहें और उसके कुप्रभावों को भी दूर किया जा सके; राज्य का कार्य कानून, व्यवस्था तथा न्याय की स्थापना ही नहीं है, अपितु सामाजिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इसका कार्य समाज में सामान्य हितों तथा समाज के सदस्यों के कल्याण के लिए विविध सेवाओं का उपलब्ध कराना भी है। कल्याणकारी राज्य के मुख्य सिद्धान्त अपेक्षाकृत सामान्यतः ये हैं: **पहला**, इस तथ्य की पहचान कि एक व्यक्ति, व्यक्ति होने के नाते, न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति का अधिकारी है; **दूसरा**, कल्याणकारी राज्य आर्थिक स्थिरता तथा प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध है, ताकि सार्वजनिक नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में प्रचण्ड उछालों तथा विफलताओं के चक्रों को दूर किया जा सके तथा निजी उद्यमों द्वारा आर्थिक अस्थिरता व पतन के भय को रोका जा सके; **तीसरा**, सार्वजनिक नीति को एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में, कल्याणकारी राज्य सम्पूर्ण रोज़गार के लिए प्रतिबद्ध है: 1930 के दशक की आर्थिक मंदी ने यह स्प-ट कर दिया था कि बेरोज़गारी कितनी विनाशकारी होती है और कि वह लोग जो काम करने के योग्य होते हैं, उन्हें उन परिस्थितियों में रोज़गार नहीं मिलता, जिन्हें न तो उन्होंने बनाया होता है और न ही उन पर उनका नियंत्रण होता है। कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ताओं ने यह मत व्यक्त किया था कि रा-ट्रीयकरण की अतिताओं पर जाए बिना सम्पूर्ण रोज़गार व्यवस्था नीतियों के दायरे में स्वतंत्र उद्यमी संरचना बनायी भी जा सकती हैं तथा संरक्षित भी की जा सकती हैं। करारोपण को समृद्धि और मन्दी के समय में समंजित किया जा सकता है, ब्याज की दरें सरकार के निर्णयों द्वारा भावी आर्थिक परिस्थितियों व आवश्यकताओं व प्रवाहों के प्रकाश में निर्धारित की जा सकती हैं, रा-ट्र के सर्वोत्तम हितों के दायरों में खरीद करने की शक्ति के पुनः वितरण के लिए वित्तीय नीतियाँ सुनिश्चित की जा सकती है, मंद सार्वजनिक कार्यों के समय में जब प्रत्यक्ष बेरोज़गारी राहत देना संभव न हो, निजी व्यापारिक संस्थानों को निवेशीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है, आवास खरीदने व आवास बनाने वाले निगमों को सरकार

दिया। राज्य हस्तक्षेप से पूंजी निवेश किया जा सकता है, जिसके बदले में उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को कम किया जा सकता है, उद्योगों में कार्य होता रहता है तथा व्यापक स्तर की बेरोज़गारी का उन्मूलन हो सकता है। उदारवाद तथा पूंजीवाद को बचाने के लिए, कीन्स ने महसूस किया कि राज्य की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा बचत दर पर नियंत्रण करना चाहिए; निवेश, लाभ, करों की दरें, मज़दूरी आदि राज्य के मुद्दें हैं। कीन्स पूंजीवाद तथा समाजवाद को परस्पर विरोधी मानने को तैयार नहीं है और न ही वे समझते हैं कि राज्य तथा व्यक्ति एक-दूसरे के प्रतिवाद है। यह स्वतंत्रता की मूल उदारवादी धारणा का अंत नहीं था, अपितु उसका विस्तार था।

दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात्, युद्ध उपरान्त समस्याओं के फलस्वरूप राज्य हस्तक्षेप कितना और अधिक ज़रूरी हो गया, इस तथ्य की पु-टि जॉन गैलब्रैथ की रचनाओं वे स्प-ट हो जाती है। अपनी रचनाओं, *दी ऐफ्लुयंट सोसाइटी (The Affluent Society)* तथा *द न्यू इन्डीस्ट्रियल स्टेट (The New Industrial State)* में उन्होंने क्लासिकी उदारवाद की परम्परागत सूझ-बूझ से मुक्ति प्राप्त के लिए तर्क दिया तथा विचारधारा की जटिलताओं से दूर रहते हुए समाजवादी तरीकों को अपनाए जाने की वकालत की। उन्होंने पूंजीवादी समाजों के कल्याण के लिए किन्हीं समाजवादी उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि विकसित देश बार-बार घटने वाले आर्थिक संकटों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें आर्थिक क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप का स्वागत करना पड़ेगा।

सारांश में 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्द्धभाग तथा 20वीं शताब्दी के पहले अर्द्ध भाग में जो सकारात्मक उदारवाद उभर कर आया, उसमें तथा क्लासिकी नकारात्मक उदारवाद में अनेक रूपों में भेद किया जा सकता है: *पहला,* यद्यपि सकारात्मक उदारवाद की मान्यता व्यक्ति की स्वायत्तता, उसके अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं में पहले की भांति बनी रहीं, तथापि अब इसका विश्वास हो गया कि व्यक्ति समाज का एक अंश है, और फिर उसकी स्वतंत्रताएँ तभी सुरक्षित हो सकती हैं, जब वह सामाजिक हित से मेल खाती होती हों - सामज को अब एक सशक्त, समस्त तथा व्यवस्थित संगठन समझा जाने लगा तथा जिसमें सभी सामाजिक वर्ग सामान्य हित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं; समाज का अपना हित होता है, उसके अपने नैतिक आयाम होते हैं तथा वैयक्तिक हित सामाजिक हित के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। *दूसरा,* न्याय, तथा समानता की भांति स्वतंत्रता कोई खोखला सामाजिक आदर्श नहीं होता, अपितु, इसका विशे-ा सार विशे-ा प्रकार की सामाजिक तथा ऐतिहासिक पृ-ठभूमि से बनता है। समाज में स्वतंत्रता परस्पर दावों का सामंजस्य होता है, जो अधिकारों की व्यवस्था के रूप में संभव हो पाते हैं और वहाँ ऐसे अधिकारों का प्रयोजन बंधनों व स्वतंत्रताओं का मिला-जुला रूप होता है: 'स्वतंत्रता बंधनों का अभाव मात्र नहीं होती, अपितु वे ऐसी आवश्यक परिस्थितियों का अस्तित्व होती है जिसमें व्यक्ति का स्वतंत्र तथा पूर्ण विकास होता है और जिन परिस्थितियों को राज्य जो वह अपने नैतिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हुए, उपलब्ध कराता है'। विवशता के माध्य की स्वतंत्रता, वह भले ही विरोधाभासी दिखाई दे, व्यवहार के आधार पर वैध समझी जाती है; इसी आधार पर स्वतंत्रता सामाजिक तथा कल्याणकारी कानून-निर्माण को उचित समझती है। यह याद रहना चाहिए कि स्वतंत्रता में समानता भी अंतर्निहित होती है। समानता ऐसा आधार प्रदान करती है, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता को एक सकारात्मक रूप मिलता है, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे की पूरक अवधारणाएँ हैं। समानता मात्र कानून के समक्ष समरूता, अथवा मात्र अवसरों की समानता अथवा व्यक्ति होने के रूप में सबके लिए समान व्यवहार समानता मात्र नहीं होती, अपितु आर्थिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप होना पड़ता है - यह एक ऐसी सोच है जिसके द्वारा राज्य धन व अवसरों की व्यापक वि-ामताओं के उन्मूलन हेतु कार्य कर सकता है। *तीसरा,* सकारात्मक उदारवाद समाज में नियंत्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है: राज्य वैयक्तिक पूंजीपति पर आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए नियंत्रण कर सकता है, श्रमिक वर्ग की दशाओं में सुधार कर सकता है,

ऋण दे सकती है - यह सब ऐसे कुछ प्रयास हैं, जो पूंजीवादी आधारों को परिवर्तित किए बिना सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने हेतु उठा सकती है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, अभाव, बीमारी तथा बुढ़ापे के विरुद्ध सुरक्षा की माँग मानववादी तर्कों के कारण ही नहीं की जाती, अपितु, इसे आर्थिक आधार पर भी उचित इस कारण ठहराया जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित न्यूनतम जीवन स्तर कम से कम लोगों को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधाएँ तो दे। ऐसी स्थिति उद्योगों में वैभव व मंदी के दायरे में ही सदैव रहती है। श्रम तथा उद्योग-प्रबंधकों के बीच सामूहिक सौदेबाज़ी और अधिक स्थिर तथा खुशहाल अर्थव्यवस्था का एक और योगदान है, क्योंकि उच्चतर मज़दूरी उद्योगें तथा कृ-ि उत्पादों के लिए बड़े-बड़े बाज़ार भी बनाती है, बशर्ते उनका आधार उच्चतर और अधिकतम उत्पादकता हो, न कि अधिक संगठित आधार पर लूट-मार हो।

कल्याणकारिता के यंत्र के माध्यम से, सकारात्मक उदारवाद ने राज्य की शक्ति को बाज़ार की शक्तियों के संचालन में कम से कम तीन दिशाओं में संशोधित हेतु प्रयोग किया हैः (i) व्यक्तियों तथा परिवारों को न्यूनतम आय का आश्वासन - भले बाज़ार में उनके काम व सम्पत्ति का अनुकूल मूल्य हो अथवा न हो; (ii) असुरक्षा के दायरे को इस प्रकार कम कर के कि व्यक्तियों तथा परिवारों को बीमारी, बुढ़ापे तथा बेरोज़गारी जैसे कुछेक सामाजिक परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध हो; (iii) बिना स्तर व वर्ग के भेद के, सभी नागरिकों को उपलब्ध सामाजिक सेवाओं का आश्वासन। कल्याणकारी राज्य का प्रभेदक लक्षण यह है कि समाज, राज्य के माध्यम से काम करते हुए, सभी व्यक्तियों को साधनों की उपलब्धिता का दायित्व लेता है और जो साधन लोगों के न्यूनतम जीवन स्तर, आर्थिक तथा सभ्य जीवन शैली जैसी सुविधाओं से सम्बंधित होते हैं तथा जिन्हें समाज के सब सदस्य अपनी अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार उनको प्राप्त करते हैं। कल्याणकारी राज्य की अद्वितीय विशे-ताएँ निम्नलिखित हैं।

### 16.3.1 कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है

कल्याणकारी राज्य में निहित मान्यता यह है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वांछनीय संस्था है, जो सकारात्मक अच्छाई को प्रोत्साहित करने में सक्षम होती है। अहस्तक्षेपी उदारवाद का यह विचार था कि सरकार प्राकृतिक शक्तियों के स्वतंत्र व्यवस्था में व्यक्ति को अकेला छोड़ते हुए सामान्य हित को बढ़ावा दे सकती है, परन्तु कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि राज्य अपनी शक्तियों के सकारात्मक प्रयोग द्वारा सामन्य कल्याण को बढ़ा सकता है। कल्याणकारी राज्य लोकतान्त्रिक राज्य को मात्र एक त्रुटि नहीं मानता, बल्कि उसे एक ऐसा यन्त्र समझता है जिसे लोग अपने सामान्य हित की वृद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं अथवा उन्हें करना चाहिए, वह राज्य जो उनकी तत्कालीन दशाओं में जिनमें वह न्याय करता है, सुधार करने का माध्यम बन सकता है; लोगों का विचार है कि राज्य उन को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कुछ सीमा तक उन्हें सामाजिक व आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकता है।

### 16.3.2 कल्याणकारी राज्य एक लोकतान्त्रिक राज्य है

कल्याणकारी, उदारवादी कल्याणकारी राज्य को एक लोकतान्त्रिक राज्य घो-ित करने का दावा करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे राज्य में कुछेक औपचारिक संस्थागत उपकरण होते हैं, जो उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक समझे जाते हैंः कोई भी राज्य जो एक कल्याणकारी राज्य हो

और संस्थागत दृ-टि से यदि वह लोकतान्त्रिक नहीं है, तो वह उदारवादी राज्य नहीं हो सकता; राज्य केवल तभी ही कल्याणकारी राज्य होगा, यदि उन्होंने औपचारिक रूप से लोकतान्त्रिक चोला पहन हो। ऐसा राज्य जो न्यूनतम आय की गारण्टी देता हो, सामाजिक विपतियों में लोगों तथा परिवारों की असुरक्षा को मिटाने का प्रयास करता हो, तथा जो सबके लिए सेवाओं की कोई अमुक मात्रा उपलब्ध कराता हो, लेकिन यदि ऐसे राज्य में लोकतान्त्रिक संरचनात्मक ढाँचा तथा राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताएँ नहीं हैं, तो ऐसे राज्य को एक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर पूर्व सोवियत संघ, जनवादी चीन तथा पूर्व पूर्वी यूरोपीय देश कम्युनिस्ट राज्य की ओर तथा जर्मनी जैसे फासीवादी देश दूसरी ओर कल्याणकारी राज्य की श्रेणी से अलग समझे जाते थे। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य शब्द पूंजीवादी देशों में उन राज्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कल्याणकारी सेवाओं रूपी सकारात्मक कार्य करते हैं तथा जहाँ औपचारिक लोकतान्त्रिक ढाँचा विद्यमान होता है

### 16.3.3 कल्याणकारी राज्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है

एक कल्याणकारी राज्य बाज़ार अर्थव्यवस्था के दायरे में काम करता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था के दायरे का अर्थ हैः उत्पादन का पूंजीवादी तरीका। अहस्तक्षेपी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल, कल्याणकारी राज्य की यह आस्था है कि बाज़ार अप्रतिबंधित परिचालन व्यक्ति के लिए भयानक (क्योंकि इससे निर्धनता, अज्ञानता, निरक्षरता अदि बढ़ी है) सिद्ध हुआ है; अर्थव्यवस्था के लिए भी इसके अनुकूल परिणाम (क्योंकि इससे व्यापारिक उछाल, मंदी, संकट तथा व्यर्थता व अकुशलता आदि बढ़ी हैं) नहीं निकले। कल्याणकारी राज्य बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था का अंत नहीं चाहता, परन्तु उसे ऐसा रूप देना चाहता है कि आर्थिक संकट भी न आ पाएँ और उत्पादकीय संभावित परिणाम भी प्राप्त किए जा सकें। कल्याणकारी राज्य का मानना है कि निर्धनता, आश्रितता, तथा आर्थिक अनुरक्षा प्रकृति तथा निर्धनों की अयोग्यता के परिणाम नहीं होती अपितु, समाज में परिवर्तनीय व्यवस्थाओं का फल होती हैं। इतिहास में पहली बार आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संसार से निर्धनता के अंत को संभव बना दिया है। आर्थिक तथा अन्य प्रकार की असुरक्षाएँ सामाजिक कारणों का फल होती हैं, जिन्हें सामाजिक रूप के उद्देश्यात्मक तरीकों से हटाया भी जा सकता है। आर्थिक असुरक्षा इन कारणों से पनपती हैः (क) अपर्याप्त क्षतिपूर्ति, (ख) दुर्घटनाओं, अस्वस्थता, बुढ़ापे आदि के कारण अपंगता अर्थात अशक्तता आती है; (ग) बेरोज़गारी। कल्याणकारी राज्य का विश्वास है कि अहस्तक्षेपी अर्थव्यवस्था का पुनः प्रतिरूपण करके तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार के नियोजन को प्रस्तुत करके ऐसी असुरक्षाओं पर काबू पाया जा सकता है। परन्तु कल्याणकारी राज्य नियोजन को किन्हीं विविध मात्रा में बाज़ार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी व्यवस्था की त्रुटियों को राज्य हस्तक्षेप द्वारा दूर करना चाहता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेता है, जिसे आज 'मिश्रित अथवा 'प्रबंधकीय' अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

### 16.3.4 कल्याणकारी राज्य समाज की एक स्थायी संस्था तथा उसका एक तटस्थ अभिकरण है

सकारात्मक उदारवाद की मान्यता है कि कल्याणकारी राज्य समाज की एक शाश्वत तथा स्थायी संस्था है। यह शक्ति का एक तटस्थ यंत्र भी है, जिसे किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह समाज के हित की प्राप्ति हेतु एक मध्यस्थ है। राज्य द्वारा कल्याणकारिता की मात्रा तथा गुणवत्ता उपलब्धता कराने की योग्यता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसकी शक्ति किन समूहों के पास है। सरकार के कार्यकर्त्ता लोगों की इच्छाओं के अनुरूप सार्वजनिक मताधिकार द्वारा बदले जा

सकते हैं। राज्य किसी वर्ग विशे-ा से जुड़ा नहीं होता। बिना स्तर तथा वर्ग के भेद किए राज्य अर्थव्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन कर सकता है कि सभी नागरिकों को सामाजिक जीवन की न्यूनतमताएँ प्राप्त हों। जैसा कि टिटमस ने कहा है, "ऐसा बड़ी तेज़ी से समझा जा रहा है कि सरकार का सही कार्य न केवल गरीबों के, अपितु समाज के सभी वर्गों के दुःखों व तनावों को दूर करना है।"

नि-क-र्षतः सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य को एक नए प्रकार का राज्य बताता है, जो अपने रूप में लोकतान्त्रिक है और जो लाभ-प्रेरित बाज़ार अर्थव्यवस्था को वांछनीय मानते हुए उसे सामाजिक ज़रूरतों के अनुरूप ढालना चाहता है, ताकि सब नागरिकों को सामाजिक कल्याण उपलब्ध हो। यह ऐसा राज्य है, जो अहस्तक्षेपी राज्य से विकसित हो कर बाज़ार अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के परिचलन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप कर पूंजी की शक्ति को नियंत्रित करता है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग लोगों को पूंजी के अत्याचार से मुक्त करते हुए उन्हें कल्याणकारिता के निश्चित स्तर का आश्वसन देता है। कल्याणकारी सुविधाएँ किन्हीं विशे-ा गुटों तक सीमित नहीं रहती, अपितु उनका सम्बन्ध पूरे समाज से होता है।